न्यूज गैलरी

'गुलाम कश्मीर पर सेना प्रमुख की टिप्पणी पर होगा विचार'

मुंबई : गुलाम कश्मीर को लेकर सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने के बयान पर रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि सरकार इसके बारे में विचार करेगी। मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इनका तो जज्बा यही है। इनका यह बोलना गलत नहीं है। सरकार इस बात पर निश्चित तौर से गौर करेगी। केंद्रीय मंत्री ने पूर्व सैनिकों की देश सेवा की सराहना भी की। इसके अलावा उन्होंने दिवंगत सैनिकों की याद में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। उल्लेखनीय है कि 11 जनवरी को सेना प्रमुख नरवाने ने कहा था कि यदि सेना को आदेश मिलता है, तो वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को फिर से हासिल करने के लिए उचित कार्रवाई करेगी। उन्होंने संसद द्वारा पारित उस प्रस्ताव का भी हवाला दिया था, जिसमें संपूर्ण जम्मू-कश्मीर को भारत का अंग बताया गया था। उन्होंने कहा कि यदि संसद चाहती है और इस सिलसिले में कोई आदेश मिलता है, तो सेना उचित कार्रवाई करेगी। बताते चलें कि फरवरी, 1994 में पीवी नरसिंह राव सरकार के दौरान संसद ने संकल्प प्रस्ताव पारित कर गुलाम कश्मीर को जम्मू-कश्मीर का क्षेत्र बताते हुए भारत का हिस्सा करार दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद दो बार साफ कहा है कि अब पाकिस्तान से कोई बातचीत केवल गुलाम कश्मीर के मसले पर ही होगी। (एएनआइ)

भारत ने पाक से समझौता एक्सप्रेस के डिब्बे मांगे

नई दिल्ली : भारत ने पाकिस्तान से वाघा में पिछले पांच महीने से खड़ी समझौता एक्सप्रेस के डिब्बे लौटाने को कहा है। अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच रेल सेवा निलंबित कर दी गई। रेलवे अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद से इस संबंध में अनुरोध किया है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हमारे (रेलवे) अनुरोध पर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के अधिकारियों से कहा है कि जितनी जल्दी हो सके वह ट्रेन के हमारे डिब्बे लौटाए।' ट्रेन के डिब्बों को अंतिम बार आठ अगस्त 2019 को इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तान ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वाघा सीमा पर समझौता एक्सप्रेस ट्रेन रोक दी थी और 117 यात्री फंस गए थे। ट्रेन को अपराह्न 12:30 पर अटारी पहुंचना था, लेकिन वह शाम 5:15 बजे पहुंची जब भारतीय रेल ने ट्रेन और अपने यात्रियों को वाघा सीमा से अटारी लाने के लिए अपना इंजन, चालक दल के सदस्यों और सुरक्षाकर्मियों को भेजा। समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के लिए दोनों देश छह महीने के अंतराल पर एक दूसरे के रेल के डिब्बों का इस्तेमाल करते हैं। (प्रेट्र)

फिटनेस मंत्र ▶ केंद्र लाया कार्यस्थल पर कर्मचारियों को तनावमुक्त करने का नुस्खा

हर संस्थान में लागू होगा योग-ब्रेक

आयुष मंत्रालय ने पांच मिनट की हल्की कसरत का प्रोग्राम तैयार किया, ट्रायल शुरू

नई दिल्ली, प्रेट्र : काम इतना करो कि हमेशा व्यस्त रहो, व्यायाम इतना करो कि हमेशा स्वस्थ रहो। इसी लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को आयुष मंत्रालय ने एक नए स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। इसी के चलते सरकारी संस्थानों और कारपोरेट जगत में जल्द ही पांच मिनट का वाई ब्रेक या योगा-ब्रेक अनिवार्य हो जाएगा। इन योगासनों से कर्मचारियों का ध्यान दुरुस्त होगा और उत्पादकता भी बढ़ेगी। इस दौरान काम के घंटों में से सिर्फ पांच मिनट की छुट्टी लेकर कुछ हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करनी होगी।

कार्यस्थल पर व्यवसायियों को तनावमुक्त और तरोताजा करने में मदद के लिए हल्के-फुल्के योगासन कारगर होने वाले हैं। ताकि विशेष रूप से डेस्क वर्क करने वाले कर्मचारी और अधिकारी घंटों एक ही अवस्था में बैठे रहकर रोगग्रस्त न हो जाएं। विगत सोमवार को आयुष मंत्रालय ने पांच मिनट के वाई ब्रेक का ट्रायल कराया। यह वाई ब्रेक मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के जरिए मंत्रालय ने विकसित कराया है। यहां के प्रख्यात योग विशेषज्ञों की देखरेख में कुछ आसान योगासनों को इसमें समाहित किया गया है।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ कारपोरेट हाउस जैसे टाटा कैमिकल्स, एक्सिस बैंक और अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल कंसल्टिंग सर्विसेज समेत करीब 15 संस्थानों ने इस ट्रायल में स्वैच्छिक रूप से हिस्सा लिया है। आयुष मंत्रालय ने इससे पहले सरकारी संस्थानों और अन्य कारपोरेट कंपनियों से अपने कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से 30 मिनट का ब्रेक करने की अपील की थी।

फिक्की ने कंपनियों को अपने कारपोरेट ऑफिसों में अपने कर्मचारियों को योग-ब्रेक देने का सर्कुलर भी जारी किया है। वाई-ब्रेक योगासनों का कोई कोर्स नहीं है। बल्कि यह एक संक्षिप्त मॉड्यूल है। इस योग प्रोटोकाल की प्रक्रिया पर करीब तीन महीने पहले दस प्रख्यात योग विशेषज्ञों ने काम शुरू किया था। अधिकारियों ने बताया कि इन हल्की-फुल्की कसरतों पर एक बुकलेट और वीडियो फिल्म भी तैयार की गई है। ताकि इन्हें कारपोरेट हाउस में दिखाया जा सके। इसके प्रभाव और दक्षता को परखने के लिए ट्रायल जारी है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि कारपोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को काम के भारी दबाव से गुजरना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए पांच मिनट का यह ब्रेक स्ट्रेस दूर करने में सहायक होगा और उनकी कंपनी की उत्पादकता भी बढ़ेगी। साथ ही कर्मचारियों को कई तरह के रोगों से भी निजात मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने खेल को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर राज्यों से मांगा जवाब

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक के पाठ्यक्रम में खेल को शामिल किया जा सकता है या नहीं इसका जवाब देने का निर्देश दिया। एमिकस क्यूरी की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस संबंध में प्रश्नावली तैयार की है।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि उन्हें अभी तक सिर्फ आठ राज्यों से ही जवाब मिले हैं, लेकिन यह आधे अधूरे और अस्पष्ट हैं। वरिष्ठ वकील ने कहा कि उन्होंने दो पेज की प्रश्नावली तैयार की है ताकि इस मामले से संबंधित मुद्दों पर राज्य जवाब दे सकें। पीठ ने शंकरनारायणन को सभी राज्यों को यह प्रश्नावली भेजने की अनुमति देते हुए उन्हें तीन सप्ताह के भीतर इसका जवाब देने का निर्देश दिया। शीर्ष

सुप्रीम कोर्ट। फाइल फोटो

अदालत प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में खेलों को शामिल करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्याय मित्र ने कहा कि उनकी प्रश्नावली में राज्य सरकारों और राज्य के शिक्षा बोर्ड से संबंधित सवाल भी हैं। इनमें खेल शिक्षा के लिए उठाए गए कदमों का विवरण मांगा गया है। इसमें यह भी पूछा गया है कि क्या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कूलों में खेलों के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए धन या मदद प्रदान करते हैं।

ट्राई के नए टैरिफ ऑर्डर पर ब्रॉडकास्टरों को फौरी राहत नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- बांबे हाई कोर्ट ने ट्राई से जवाब दाखिल करने को कहा, अगली सुनवाई 22 को
- ऑर्डर में 153 रुपये में 200 फ्री चैनल व 12 रुपये में पेड चैनल दिखाने का आदेश

ट्राई के नए टैरिफ ऑर्डर के खिलाफ बांबे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले ब्रॉडकास्टरों को फिलहाल राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मंगलवार को ट्राई से ब्रॉडकास्टरों की आपत्तियों पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसके आधार पर वह 22 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगा। इस बीच भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नए टैरिफ ऑर्डर को उचित ठहराते हुए इसे सभी के लिए न्यायसंगत बताया है। नया टैरिफ ऑर्डर एक मार्च से लागू होना है।

याचिकाकर्ता एवं ब्रॉडकास्टरों की प्रतिनिधि संस्था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने यह कहते हुए नए टैरिफ ऑर्डर का विरोध किया है कि इससे उनका रेवेन्यू कम होगा और ब्रॉडकास्टिंग उद्योग के विकास पर बुरा असर पड़ेगा। फाउंडेशन में टीवी ब्रॉडकास्टरों के अलावा फिल्म एवं टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड तथा सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया शामिल हैं।

नए टैरिफ ऑर्डर में ब्रॉडकास्टरों को 130 रुपये (कर समेत 153 रुपये) में 100 के बजाय 200 फ्री टू एयर चैनल दिखाने को कहा गया है। इसमें पेड चैनलों की नई दरें भी निर्धारित की गई हैं और ब्रॉडकास्टरों से 15 जनवरी तक इन सभी दरों को टीवी पर सार्वजनिक करने को कहा गया है। याचिका में इस अंतिम तिथि को स्थगित करने की भी मांग की गई है।

नया टैरिफ ऑर्डर ट्राई द्वारा दिसंबर 2018 में जारी और फरवरी 2019 से लागू पहले टैरिफ ऑर्डर का संशोधित रूप है। पहले टैरिफ ऑर्डर में ब्रॉडकास्टरों को 100 फ्री टू एयर चैनल दिखाने के लिए ग्राहकों से नेटवर्क कैपेसिटी फीस के रूप में 130 रुपये वसूलने (कर समेत 153 रुपये) की छूट दी गई थी। उसने छह महीने की परामर्श प्रक्रिया के बाद अब अपने पहले टैरिफ ऑर्डर में संशोधन कर नया ऑर्डर निकाला है। नए टैरिफ ऑर्डर के मुताबिक 200 फ्री टू एयर चैनलों में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्धारित अनिवार्य चैनलों को नहीं गिना जाएगा। जिन घरों में एक व्यक्ति के नाम पर एक से ज्यादा टीवी हैं, वहां अन्य टीवी सेट्स के लिए 40 फीसद से अधिक नेटवर्क कनेक्शन फीस नहीं वसूली जा सकती है।

इसी प्रकार पेड चैनलों की बकेट में किसी भी चैनल का मूल्य बकेट के मूल्य के डेढ़ गुने से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। बकेट में शामिल किसी भी पेड चैनल की दर उसमें शामिल दूसरे चैनलों की औसत दर के तीन गुना से ज्यादा नहीं हो सकती।

बांग्लादेश की नाराजगी हुई दूर, सूचना-प्रसारण मंत्री भारत आए

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- दोनों देशों के बीच कारोबार सहयोग पर गठित समूह की बैठक आज
- बंग बंधु पर एक फिल्म बनाने के समझौते पर भी किए हस्ताक्षर

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनसीआर) में बार-बार अपना नाम लिए जाने से नाराज बांग्लादेश को मनाने में अंततः भारत सफल रहा है। बांग्लादेश के सूचना-प्रसारण मंत्री हसन महमूद न सिर्फ मंगलवार को भारत पहुंचे, बल्कि उन्होंने यहां एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किया। बुधवार को दोनों देशों के बीच कारोबार सहयोग पर गठित समूह की बैठक होगी।

हसन महमूद ने सूचना-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर के साथ बंग बंधु पर एक फिल्म बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर भी किया। भारत व बांग्लादेश के साझा सहयोग से बनने वाली इस फिल्म का निर्देशन श्याम बेनेगल करेंगे। महमूद ने इस समझौते के बाद रायसीना डायलॉग में भी हिस्सा लिया। सनद रहे कि पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्री शहरयार आलम के रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेना था, लेकिन उन्होंने अंतिम समय में इसे टाल दिया था। दरअसल, जब से भारतीय संसद में सीएए पारित हुआ है, उसके बाद से बांग्लादेश के नेताओं

बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हसन महमूद (दाएं) ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर से मुलाकात की। एएनआइ

के तीन भारतीय दौरों को रद किया गया। माना जाता है कि बांग्लादेश ने नागरिकता संसोधन कानून (सीएए) से नाराज होकर ही यह फैसला किया था। वैसे भारत ने उसे आश्वस्त किया था कि सीएए मौजूदा शेख हसीना सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाती है।

मोदी ने किए घरेलू बजट के 'टुकड़े-टुकड़े' : राहुल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- जीडीपी गिरावट, बेरोजगारी व महंगाई की हालत को आर्थिक आपातकाल जैसा बताया
- कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से की मंहगाई पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग
- प्रियंका बोलीं, सरकार ने जेब काट कर पेट पर लात मार दी है

राहुल गांधी। फाइल

लगाया आरोप

3.15 फीसद से बढ़कर खुदरा महंगाई 7.35 फीसद हो गई

60 फीसद बढ़ गए सब्जियों और 15 फीसद दाल के दाम

2019 में 16 लाख नौकरियों के कम होने का भी आरोप लगाया

कांग्रेस ने आर्थिक सुस्ती के बीच महंगाई में भारी इजाफे को लेकर सरकार पर चौतरफा हमला बोला है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी ने देशवासियों के घरेलू बजट के 'टुकड़े-टुकड़े' कर दिए हैं। वहीं पार्टी ने महंगाई पर प्रधानमंत्री से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करते हुए कहा है कि बेरोजगारी और महंगाई ही मोदी सरकार का देश को दिया अब तक का दो तोहफा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि भाजपा सरकार ने तो आम लोगों की जेब काट कर उनके पेट पर लात मार दी है।

महंगाई पर मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी ने उसी टुकड़े-टुकड़े नारे का सहारा लिया जिसे भाजपा अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करती है। राहुल ने ट्वीट कर कहा 'कमरतोड़ महंगाई, जानलेवा बेरोजगारी और गिरती जीडीपी ने आर्थिक आपातकाल की स्थिति बना दी है। सब्जी, दाल, खाने का तेल, रसोई गैस व खाद्य पदार्थों की महंगाई ने गरीब के मुंह का निवाला छीन लिया है। मोदी जी ने देशवासियों के घरेलू बजट के टुकड़े-टुकड़े कर दिए हैं।'

प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट के जरिए निशाना साधा। उन्होंने कहा 'सब्जियों, खाने-पीने की चीजों के दाम आमलोगों की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। जब सब्जी, तेल, दाल और आटा महंगा हो जाएगा तो गरीब खाएगा क्या? ऊपर से मंदी की वजह से गरीब को काम भी नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार ने तो जेब काट कर पेट पर लात मार दी है।'

वहीं, कांग्रेस की ओर से हमला बोलते हुए मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कांफ्रेंस कहा कि 2012-13 के बाद महंगाई पहली बार इतनी चरम सीमा पर पहुंची है। तब पीएम मोदी ने कहा था कि महंगाई वह डायन है जो हर रोज बढ़ती जाती है और इसीलिए अबकी बार महंगाई पर वार। मगर अब पीएम महंगाई पर चुप हैं। खुदरा महंगाई जुलाई 2019 में 3.15 फीसद से बढ़कर दिसंबर में दोगुनी से ज्यादा 7.35 फीसद हो गई है और जनवरी में यह आठ फीसद का आंकड़ा छू रही है।

सब्जियों के दाम 60 फीसद और दालों के 15 प्रतिशत से अधिक बढ़ गए हैं। दूध, मीट और मछली के साथ मसालों के दाम में भी भारी में इजाफा हुआ है। प्याज 2014 में आठ रुपये किलो था जो आज 85 रुपये किलो से ज्यादा है। इसीलिए कांग्रेस की मांग है कि पीएम सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्षी दलों को 30 दिन के भीतर महंगाई कम करने का रोडमैप बताएं।

सुरजेवाला ने कहा कि एक ओर जहां महंगाई बढ़ रही है वहीं दूसरी तरफ भाजपा की आय में भी 1400 फीसद का इजाफा हुआ है।

महंगाई के साथ बेरोजगारी पर आरबीआइ के आंकड़ों के सहारे सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि 2019-20 में 16 लाख नौकरियां कम हो गई हैं। ताजा आंकड़े यह भी बता रहे हैं कि इस साल करीब 50,000 सरकारी नौकरियां भी कम हो जाएंगी। सुरजेवाला ने कहा कि लोगों से जुड़े इन मुददों का हल निकालने का काम करने की बजाय सरकार का काम शासन करना नहीं विभाजन करना बन गया है।

दुर्लभ बीमारी के मरीजों को 15 लाख तक की मदद देगी सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार दुर्लभ बीमारियों के एकमुश्त इलाज के लिए 15 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद देगी। बहुप्रतीक्षित दुर्लभ रोग नीति मसौदे में राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत इसका प्रावधान किया गया है।

दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा सोमवार को जारी किया गया। इसके तहत लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रावधानों के अनुसार 40 प्रतिशत आबादी भी इसके लिए पात्र होगी। दुर्लभ बीमारियों में किडनी और लीवर प्रत्यारोपण भी शामिल है। केंद्र सरकार की इस योजना से कई जरूरतमंदों को लाभ पहुंचेगा। फिलहाल कई दुर्लभ बीमारियों में अधिक खर्च होने के कारण लोगों को इलाज में आर्थिक रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का इरादा कुछ चिकित्सा संस्थानों को दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में अधिसूचित करने का इरादा है। इनमें

- दुर्लभ रोग नीति के मसौदे में एकमुश्त इलाज के लिए प्रावधान
- बीपीएल परिवारों और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत पात्रों को होगा फायदा

एम्स, नई दिल्ली, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ शामिल हैं।

मसौदा नीति के अनुसार इन केंद्रों में मरीजों के उपचार का खर्च ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए प्राप्त दान से पूरा किया जाएगा। मंत्रालय ने मसौदा नीति अपनी वेबसाइट पर डाल दी है और 10 फरवरी तक इस पर टिप्पणी और सुझाव मांगे गए हैं। मसौदे में कहा गया है कि सरकार दुर्लभ बीमारियों के मरीजों के इलाज पर आने वाले खर्च के लिए दान करने वाले स्वैच्छिक लोगों और कॉर्पोरेट घरानों की खातिर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित कर वैकल्पिक वित्त पोषण तंत्र बनाने का प्रयास करेगी।

ट्रेनों में 2022 से मांग पर सिनेमा, वीडियो

नई दिल्ली, प्रेट्र : 2022 से यात्रा के दौरान रेल यात्री सिनेमा, शो, शैक्षणिक कार्यक्रम, वीडियो जैसी मनोरंजन सेवाओं का निर्बाध आनंद उठा सकेंगे। रेलवे सार्वजनिक उपक्रम रेलटेल की ओर से मंगलवार को बताया गया कि यह पेड और अनपेड दोनों रूपों में उपलब्ध रहेगा।

सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने जी एंटरटेनमेंट की सहयोगी मार्गो नेटवर्क को डिजीटल एंटरटेनमेंट सेवा प्रदाता (डीईएसपी) के रूप में चुना है। मार्गो नेटवर्क ट्रेनों और स्टेशनों में मांग पर कंटेंट (सीओडी) मुहैया कराएगा।

रेलटेल ने कहा है, 'अगले दो वर्षों में भारतीय रेलवे की सभी प्रीमियम, एक्सप्रेस, मेल ट्रेनों और उपनगरीय ट्रेनों में सीओडी उपलब्ध होगा। सिनेमा, शो, शैक्षणिक कार्यक्रम जैसे कंटेंट 10 वर्षों के लिए ठेके पर पेड और अनपेड दोनों रूपों में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें शुरू के दो वर्ष लागू करने के होंगे।'इस परियोजना में रेलटेल चलती ट्रेनों में स्थापित मीडिया सर्विस के माध्यम से विभिन्न प्री-लोडेड बहु-भाषी कंटेंट (सिनेमा, संगीत, वीडियो, सामान्य मनोरंजन, जीवनशैली) मुहैया कराएगा।, जिसके बाद लोग मनोरंजन भी कर पाएंगे।

जब अमित शाह ने उड़ाई पतंग...

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (दाएं से दूसरे) ने मंगलवार को गुजरात के अहमदाबाद में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आयोजित उत्तरायण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पतंगबाजी में भी हाथ आजमाया। पतंगबाजी करते शाह को देखने के लिए लोग आसपास के घरों की छतों पर उमड़े नजर आए। गुजरात में यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। त्योहार वाले दिन लोग पतंगें उड़ाने के साथ खुशी मनाते हैं। प्रेट्र

लड़कियों का सरकारी लड़कों का निजी स्कूल में प्रवेश कराते हैं लोग

नई दिल्ली, प्रेट्र : चार से आठ वर्ष आयु वर्ग के 90 फीसद से अधिक बच्चे किसी ने किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या अधिक है। मंगलवार को जारी शिक्षा के स्तर पर 14वीं वार्षिक रिपोर्ट (एएसईआर) में यह जानकारी दी गई है। वर्ष 2019 के लिए एएसईआर की यह रिपोर्ट 24 राज्यों के 26 जिलों में कराए गए सर्वे पर आधारित है। सर्वे में चार से आठ वर्ष आयु वर्ग के 36 हजार बच्चों को शामिल किया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, 'चार से आठ वर्ष आयु वर्ग के 90 फीसद से ज्यादा बच्चे किसी ने किसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेते हैं। सर्वेक्षण के लिए चुने गए जिलों में यह प्रतिशत उम्र के साथ बढ़ता है। चार वर्ष की आयु में 91.3 फीसद बच्चों ने प्रवेश लिया, लेकिन आठ वर्ष की आयु के बच्चों में यह प्रतिशत 99.5 फीसद रहा।' हालांकि समान उम्र के बच्चों में इस बात का काफी अंतर देखा गया कि उनका प्रवेश कहां हुआ। उदाहरण के तौर पर पांच वर्ष के 70 फीसद बच्चे आंगनबाड़ी या प्री-प्राइमरी कक्षा में है, लेकिन 21.6 फीसद पहले से कक्षा एक में दाखिला ले चुके हैं।

छह वर्ष के 32.8 फीसद बच्चे आंगनबाड़ी या प्री-प्राइमरी कक्षाओं में हैं जबकि 46.4 फीसद कक्षा एक में और 18.7 फीसद कक्षा या ऊंची कक्षाओं में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 'छोटे बच्चों में भी लैंगिक असमानता साफ तौर पर देखी जा सकती है क्योंकि सरकारी स्कूलों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों के प्रवेश की संख्या अधिक है और निजी संस्थानों में लड़कियों के मुकाबले लड़कों के प्रवेश की संख्या अधिक है।'

कह के रहेंगे — माधव जोशी

पीएम से सवाल पूछने के लिए छात्रों में जबरदस्त उत्साह

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

'परीक्षा पे चर्चा'

- अब तक करीब तीन लाख छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन, दो लाख से ज्यादा ने किए सवाल भी
- 20 जनवरी को होगी चर्चा, पिछले साल सिर्फ सवा लाख बच्चों ने ही कराया था रजिस्ट्रेशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फाइल

दसवीं और बारहवीं के बोर्ड की परीक्षाएं अगले महीने से शुरू हो रही हैं। ऐसे में बच्चों में परीक्षा को लेकर किसी तरह का तनाव हावी हो, इससे पहले ही प्रधानमंत्री उन्हें इस तनाव को भगाने की टिप्स देते नजर आएंगे। 'परीक्षा पे चर्चा' पर पीएम का यह कार्यक्रम 20 जनवरी को होगा। छात्रों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अब तक देश भर के करीब तीन लाख छात्र इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इनमें से करीब दो लाख बच्चों ने पीएम से सवाल भी किया है। हालांकि कार्यक्रम में करीब दो हजार बच्चों को ही शामिल होने का मौका मिलेगा। इनमें से करीब 18 से 20 बच्चे सवाल भी पूछ सकेंगे।

प्रधानमंत्री के साथ 'परीक्षा पे चर्चा' में शामिल होने को लेकर छात्रों का यह रुझान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मांगे गए ऑनलाइन आवेदन के दौरान सामने आया है। इस दौरान छात्रों के चयन का जो आधार तय किया गया, वह निबंध प्रतियोगिता के जरिए होना है। इसमें छात्रों को पांच अलग-अलग विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना था। इस दौरान जिस बच्चे का निबंध सबसे अच्छा होगा, उन्हें ही इस कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है। हालांकि छात्रों के चयन की यह जिम्मेदारी राज्यों को दी गई है। इसके तहत प्रत्येक राज्य का एक कोटा तय किया गया है, जो उस राज्य में कक्षा नौ से बारहवीं तक के छात्रों की संख्या के आधार पर तय की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस पूरे कार्यक्रम के लिए करीब छह करोड़ रुपये का बजट भी तय किया है, जो बाहर से आने वाले बच्चों के रुकने और आने-जाने पर खर्च होगा।

गौरतलब है कि छात्रों के साथ परीक्षा से पहले पीएम का इस तरह से रूबरू होने का यह तीसरा साल है। इसकी शुरुआत 2018 से की गई थी। पिछले साल में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी करीब सवा लाख छात्रों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए थे।

पढ़ाई-लिखाई और सेहत से जुड़े सबसे ज्यादा सवाल : इस बीच पीएम के साथ 'परीक्षा पे चर्चा' के दौरान छात्रों ने जो सवाल भेजे है, उनमें बड़ी संख्या में सवाल पढ़ाई- लिखाई और सेहत से जुड़े है। सूत्रों की मानें तो इनमें से कुछ सवाल मौजूदा राजनीतिक मुद्दों से भी जुड़े हैं, लेकिन जैसा कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से गैर-राजनीतिक होता है, ऐसे में इस तहत के सवालों को शामिल करना मुश्किल है।

इन विषयों पर लिखने थे निबंध : 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छात्रों से जिन पांच विषयों पर निबंध मांगे गए थे, उनमें कृतज्ञता एक महान गुण है, आपकी आकाक्षांओं से संवरता है आपका भविष्य, परीक्षा का मूल्यांकन, हमारे कर्तव्यों पर आपके विचार, संतुलन है फायदेमंद जैसे विषय शामिल थे।

पहली बार कार्यक्रम की एंकरिंग करेंगे स्कूली बच्चे : पीएम की छात्रों के साथ होने वाली 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम की इस बार जो खासियत होंगी, उनमें इस बार दो स्कूली बच्चे एंकरिंग करते दिखेंगे। यह बच्चे केंद्रीय विद्यालय के होंगे। इनके चयन की फिलहाल प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले एंकरिंग करने के लिए किसी बड़े चेहरे को बुलाया जाता था। लेकिन इस बार बच्चों के कार्यक्रम में बच्चे ही एंकरिंग करते दिखेंगे।

REUNION IAS
IAS V.K.TRIPATHI PCS
NEW BATCHES
सामान्य अध्ययन-II (मुख्य परीक्षा)
राजव्यवस्था
POLITY (MAINS)
से कक्षा प्रारम्भ... 20 JAN 2020 | 11:30 AM 2:00 PM
GS (प्रारम्भिक परीक्षा)
राजव्यवस्था
POLITY (PT) 20 JAN 2020 | 6:15 PM 8:15 PM
OFFLINE / ONLINE CLASSES
B-11, 1st FLOOR, IN FRONT OF MEERUT SWEETS, MUKHERJEE NAGAR DELHI-9
9999421659-58